उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
मुख्यमंत्री आवास, न्यू कैंट रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 12 नवम्बर, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–04(11/45)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को बन्नू स्कूल ग्राउण्ड, रेसकोर्स में एच.एन.एन. चैनल द्वारा आयोजित पुलिस वीरता सम्मान– 2017 में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पुलिस कठिन परिस्थितियों में कार्य करती है। एच.एन.एन चैनल ने पुलिस के जवानों को सम्मानित किया। यह उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए राज्य के 156 पुलिस थानों के लिए विशेष पुलिस सहायता निधि प्रदान की जा रही है। इस वर्ष तीन करोड़ रूपये की निधि से शुरूवात की है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने एच.एन.एन. चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पुलिस के जवानों को पुलिस वीरता सम्मान –2017 से सम्मानित किया। जो जवान सम्मानित किये गये उनमें एस.टी.एफ. देहरादून के उप निरीक्षक आशुतोष सिंह, सी. पी.यू देहरादून के उपनिरीक्षक दीवान सिंह ग्वाल, उप निरीक्षक महिपाल सिंह, उधम सिंह नगर से हेड कांस्टेबल जगत सिंह बेलवाल, रूद्रपुर से पुलिस आरक्षी महेन्द्र सिंह, काठगोदाम से पुलिस आरक्षी अम्बादत्त पाण्डे, हरिद्वार पी.ए.सी के कांस्टेबल विशम्बर दत्त जोशी, एस.डी.आर.एफ के कांस्टेबल विजय सिंह, नागरिक पुलिस देहरादून के कांस्टेबल आशा लाल, देहरादून के यातायात कांस्टेबल विजय प्रसाद एवं देहरादून की महिला कांस्टेबल मनाली राठी शामिल हैं।

इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय भट्ट, सांसद श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी, विधायक/मेयर श्री विनोद चमोली, विधायक श्री खजान दास, श्री देशराज कर्णवाल, एडीजी श्री अशोक कुमार, एच.एन.एन चैनल के श्री अमित शर्मा एवं श्री विनीत शर्मा आदि उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 12 नवम्बर, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–03(11/44)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य स्थापना समारोह शृंखला के अंतर्गत 5 नवम्बर को आयोजित ''रैबार'' कार्यक्रम काफी सफल रहा है। ''रैबार'' के आयोजन से राज्य को निश्चित रूप से लाभ होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के गौरव, जो देश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर सेवाएँ दे रहे हैं, को कार्यक्रम में आमन्त्रित किया गया था। लगभग 10 घण्टे लगातार कई विषयों पर मंथन हुआ। उन्होंने कहा कि सभी अनुभवों को इकट्ठा कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।

''रैबार'' कार्यक्रम से हुए त्वरित लाभ बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के लिए कोस्ट गार्ड का रिक्रूटिंग सेंटर स्वीकृत हो गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय तकनीकि अनुसंधान संगठन (एन.टी.आर.ओ.) का साईबर सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र तीन माह में राज्य में खुलने जा रहा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री अश्विनी लोहानी द्वारा राज्य में रेलवे सेवाओं में सुधार का आश्वासन मिला है। सेना के द्वारा राज्य के सीमान्त एवं सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने हेतु 4 करोड़ अखरोट और चिलगोजे के पेड़ लगाए जाएंगे। इसके लिए नर्सरी भी तैयार कर दी गयी हैं। ''रैबार'' कार्यक्रम में, राज्य की जिलेवार मैपिंग करवा कर क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार योजनाएं बनाना एवं पाठ्यक्रम में पर्यटन और हॉर्टिकल्चर को जोड़ना जैसे कई अन्य बहुत अच्छे सुझाव भी प्राप्त हुए हैं।

देहरादून 12 नवम्बर, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–02(11/43)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को राज्य सरकार द्वारा बन्द नहीं किया गया है। योजना के अंतर्गत जिस कम्पनी के साथ अनुबंध किया गया था, निश्चित रूप से उस पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही इसमें यदि कोई अधिकारी संलिप्त होगा तो निश्चित रूप से उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना से आच्छादित मरीजों पर होने वाले चिकित्सकीय व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को निर्देश दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े मरीजों का ईलाज किया जाए, इस बीच ईलाज में किया गया व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील और गम्भीर है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही अक्षम्य होगी।

अपने लखनऊ दौरे की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गृहमंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण योजना का लाभ निश्चित रूप से उत्तराखण्ड को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से हुई भेंटवार्ता सकारात्मक रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी भी लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करना चाहते हैं।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 12 नवम्बर, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–01(11/42)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता मिलन हॉल में क्षय रोगियों के उपचार के लिए नई उपचार पद्यति 'डेली रिजीम' का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कार्यक्रम में उपस्थित कुछ क्षय रोगियों को नई उपचार पद्धति की दवाइयां देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

'लॉच ऑफ डेली रेजीम फॉर टीबी ट्रीटमेंट' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि 2025 तक भारत को ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करना है। उत्तराखण्ड की जागरुकता के स्तर को देखते हुए राज्य में यह लक्ष्य 2024 तक पाया जा सकता है। क्षय रोग अब किसी डर का विषय नहीं है और चिकित्सा शास्त्रीयों ने इस पर विजय प्राप्त कर ली है। परंतु इस रोग के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है और इसका चिकित्सकीय परामर्श के साथ नियमित उपचार बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए सरकार गंभीर है और इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में पौड़ी मुख्यालय में प्रदेश के कुल 12 अस्पतालों में टेली रेडियोलॉजी की सेवा शुरू कर दी गई है और शेष 23 अस्पतालों में जल्द शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में भी टेली रेडियोलॉजी और टेली मेडिसिन का प्रयोग दूरस्थ क्षेत्रों में उपचार पहुंचाने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि तकनीकी के प्रयोग से हमें हिचकना नहीं चाहिए चिकित्सा क्षेत्र में शोध कार्य निरंतर चलते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में युवा पीढ़ी पहले की तुलना में अधिक अपडेट है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं सहित सभी युवाओं से कहा कि वे सीधे फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं।

विशिष्ट अतिथि के रुप में उपस्थित खटीमा के विधायक श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले सात–आठ माह में शासन प्रशासन की कार्य प्रवृत्ति में बहुत सुधार आया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि स्वास्थ्य विभाग के लोग पूर्ण निष्ठा के साथ जुड़कर प्रदेश से क्षय रोग का नाश करेंगे।

मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य सलाहकार डॉ.नवीन बलूनी ने कहा कि पहाड़ों में डॉक्टरों की तैनाती से ओपीडी सेवा में आने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। 5 जिला अस्पताल डिजिटलाइज हो गए हैं जिससे उनकी मॉनीटरिंग आसान हो गई है। सरकार एक ठोस कार्य योजना बनाकर डॉक्टरों की कमी को पूरा करने का प्रयास कर रही है और शीघ्र ही लोक सेवा आयोग से डॉक्टरों की भर्ती के साक्षात्कार भी शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से सभी जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और बेस अस्पतालों में 2–2 वेंटिलेटर वाले चार बेड के आईसीयू खोलने की योजना बना ली गई है।

राज्य क्षय नियन्त्रण अधिकारी डॉ.बी.सी.काला ने बताया कि एचआईवी और ड्रग रेजिस्टेंट मरीजों के कारण ट्यूबरक्लोसिस से लड़ने की चुनौती जटिल हो गई है। पहले डॉट्स कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति सप्ताह 3 दिन ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयां दी जाती थी जबकि प्राइवेट अस्पताल प्रतिदिन दवाइयों के डोज देते थे। इलाज में एकरूपता लाने और ड्रग रेजिस्टेंस की समस्या को दूर करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइड लाइन के अनुसार अब से नई प्रक्रिया के अंतर्गत क्षय रोगी को प्रतिदिन फिक्स्ड डोज दिया जाएगा। पहले की 7–8 गोलियों के स्थान पर अब मरीज को केवल दो या तीन गोलियां खानी होगी।

स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ.अर्चना ने बताया कि पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत डेली रेजीम उपचार पद्धती प्रारंभ की जा रही है। इस पद्धति के शुरू होने पर प्रदेश से ट्यूबरक्लोसिस का समूल नाश संभव हो सकेगा। इस पद्धति के लिए सभी जनपदों में प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया है और औषधियां पहुंचा दी गई हैं। उन्होंने बताया कि टीवी नेट डायग्नोस्टिक तकनीक जो पहले प्राइवेट अस्पतालों में मरीज को 2 से रू.3000 खर्च करने पर मिलती थी अब प्रदेश के 9 जनपदों में सरकारी अस्पताल में उपलब्ध करा दी गई है। शेष 4 जनपद पौड़ी टिहरी उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में 3 महीने में उपलब्ध करा दी जाएगी।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग